अनियमितताएं | निर्माणाधीन थाना भवन पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने ठेकेदार और विभाग की भूमिका पर जताई आशंका

दीवारों में दरारें, गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों कटघरे में

शहपुरा, नवभारत। जनपद पंचायत मेंहदवानी में निर्माणाधीन थाना भवन का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही विवादों में घिरता नजर आ रहा है। भवन की गुणवत्ता, निर्माण सामग्री, सुरक्षा मानकों और पारदर्शिता को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं और जिम्मेदार विभाग पूरे मामले में आंखें मूंदे बैठा है।

ग्रामीणों के अनुसार थाना भवन का निर्माण कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका है, लेकिन भवन की कई दीवारों में दरारें दिखाई दे रही हैं। कुछ स्थानों पर दीवारों का निर्माण टेढ़ा-मेढ़ा नजर आ रहा है, जिससे भवन की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि निर्माणाधीन अवस्था में ही यह स्थिति है तो भवन पूर्ण होने के बाद उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री भी मानकों के अनुरूप नहीं है। रेत, सीमेंट और ईंटों के अनुपात तथा गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी कर केवल औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

बिना सेफ्टी किट काम कर रहे मजदूर

निर्माण स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। मौके पर काम कर रहे मजदूर बिना हेलमेट, ग्लव्स और अन्य सुरक्षा उपकरणों के कार्य करते देखे जा रहे हैं। ऐसे में किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी किसकी होगी, यह बड़ा सवाल बन गया है।

कार्यदायी एजेंसी और ठेकेदार की जानकारी भी नहीं

स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य किस एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है और ठेकेदार कौन है, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब करोड़ों रुपये के शासकीय निर्माण कार्य में पारदर्शिता ही नहीं होगी तो निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लोगों ने आशंका जताई है कि विभाग, ठेकेदार और कार्यदायी एजेंसी की जवाबदेही से बचने के लिए जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।

जांच की मांग, जिम्मेदारों से कार्रवाई की अपेक्षा

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की तकनीकी जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता, उपयोग की गई सामग्री, स्वीकृत लागत और निर्माण प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराई जाए। यदि किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित ठेकेदार, कार्यदायी एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

सूचना बोर्ड नहीं, आखिर क्या छिपाना चाहता है विभाग?

सबसे बड़ा सवाल निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड के न होने को लेकर उठ रहा है। सामान्यत: किसी भी शासकीय निर्माण कार्य के प्रारंभ होते ही स्थल पर सूचना बोर्ड लगाया जाता है, जिसमें स्वीकृत राशि, निर्माण एजेंसी, ठेकेदार का नाम, कार्य अवधि, संबंधित अधिकारियों के नाम और संपर्क नंबर सहित अन्य जानकारियां अंकित रहती हैं। लेकिन मेंहदवानी थाना भवन निर्माण स्थल पर ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद परियोजना से जुड़ी मूलभूत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इससे यह संदेह और गहरा हो रहा है कि कहीं निर्माण कार्य से जुड़े तथ्यों को जानबूझकर छिपाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा।

अजय राय बने करंजिया के प्रभारी बीईओ

करंजिया, नवभारत 31 मई। करंजिया जनपद मुख्यालय में पदस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) चिंताराम कुशराम के 31 मई को सेवानिवृत्त होने के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी का प्रभार अजय राय को सौंपा गया है। कलेक्टर के आदेशानुसार अजय राय, जो वर्तमान में बीआरसी तथा उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं, को करंजिया विकासखंड शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके प्रभार ग्रहण करने के साथ ही करंजिया के शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी अब उनके नेतृत्व में संचालित होगी।

सब इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे मौके पर, जांच जारी

नवभारत उमरिया 31 मई। पुलिस लाइन से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना रविवार शाम करीब 5 बजे घटित हुई।

मृतक की पहचान एसआई विजय सिंह रावत के रूप में हुई है। वह पुलिस लाइन में आर्म्स शाखा प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। इस दुखद घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है।

मामले की जांच की जा रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस विभाग ने सभी कर्मियों को तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी है।

अवैध मुरुम का उत्खनन करते जेसीबी जब्त

कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होगा प्रकरण

डिंडौरी, नवभारत 31 मई। जिला कलेक्टर अंजु पवन भदौरिया के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 31 मई को खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्राम छांटा बैगानटोला, तहसील एवं थाना डिंडौरी क्षेत्र में अवैध रूप से मुरुम का उत्खनन करते एक जेसीबी मशीन को जब्त किया।

जानकारी के अनुसार, जेसीबी क्रमांक एमपी 52 डीए 0254 मौके पर बिना वैध अनुमति के मुरुम उत्खनन करते पाई गई। वाहन का चालक रामचरण मरावी तथा वाहन स्वामी ठाकुर सिंह निवासी देवरी, समनापुर बताए गए हैं। खनिज विभाग द्वारा जब्त वाहन को सुरक्षार्थ पुलिस थाना कोतवाली डिंडौरी में खड़ा कराया गया है।

निरंतर जारी रहेगी कार्रवाई-अधिकारियों ने बताया कि संबंधित वाहन के विरुद्ध खनिज नियमों के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तथा प्रकरण को सुनवाई हेतु न्यायालय कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशासन ने

स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अमरपुर भाजपा मंडल तीसरी बार जिले में प्रथम

मन की बात कार्यक्रम में बादशाहत बरकरार

अमरपुर नवभारत 31 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी मन की बात कार्यक्रम में भाजपा मंडल अमरपुर ने पुन: बाजी मारते हुए लगातार डिंडौरी जिले में प्रथम स्थान पर बरकरार हैं।

जानकारी के अनुसार भाजपा मंडल अमरपुर के ऊर्जावान एवं युवा भाजपा मंडल अध्यक्ष आकाश नामदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा मंडल अमरपुर में 51 मतदान केंद्र आते हैं। जिसमें मण्डल का एक एक कार्यकर्ता तन मन से काम करता हैं। कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास और परिश्रम से ये उपलब्धि मण्डल को मिली हैं। पिछले समय भी मण्डल अमरपुर मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश में 103वें एवं डिंडौरी जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहा था। उसी प्रकार प्रधानमंत्री की 134 वें मन की बात कार्यक्रम में भी भाजपा मंडल अमरपुर प्रदेश में 130 वें एवं जिले में पुन: प्रथम स्थान प्राप्त किया हैं।

मंडल अध्यक्ष ने सभी का जताया आभार

इस उपलब्धि के लिए भाजपा मंडल अध्यक्ष आकाश नामदेव ने भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं, जिसमें सभी मण्डल पदाधिकारी, सभी शक्ति केंद्र के प्रभारी, सभी पंच परमेश्वर एवं सभी मतदान केंद्रों के त्रिदेवों का हृदय के गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपील की हैं कि आगामी समय में भी भाजपा के प्रत्येक कार्यक्रम में अपनी भागीदारी कर मण्डल अमरपुर को शिखर पर रखेंगे।

शहपुरा में प्रधानमंत्री का 'मन की बात' कार्यक्रम उत्साहपूर्वक सुना गया

शहपुरा नवभारत 31 मई। नगर के श्री राम मंदिर वार्ड, बूथ क्रमांक 85 में रविवार को प्रधानमंत्री के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, समाजसेवियों एवं मातृशक्ति ने सहभागिता करते हुए प्रधानमंत्री के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। इस अवसर पर समाजसेवी एवं पार्षद सुरेन्द्र साहू, नारायण कछवाहा सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा देश के विकास, सामाजिक जागरूकता, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्तिकरण तथा जनभागीदारी से जुड़े विषयों पर व्यक्त विचारों को सुना गया।

विभिन्न वर्गों को प्रेरित करने का माध्यम बना-उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों को प्रेरित करने का माध्यम बन चुका है। इसके जरिए

देशभर में हो रहे सकारात्मक कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचती है तथा नागरिकों में राष्ट्र निर्माण के प्रति नई ऊर्जा का संचार होता है। कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति एवं नागरिकों ने प्रधानमंत्री के संदेशों की सराहना करते हुए उन्हें जनहित और समाजहित से जुड़ा बताया।

बड़े टोला में बूंद-बूंद पानी के लिए भटक रहे ग्रामीण

करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद पेयजल संकट बरकरार, दूषित पानी के सेवन से बीमारियों का खतरा बढ़ा

अमरपुर नवभारत 31 मई। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां एक ओर सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं डिंडौरी जिले के अमरपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मौहारी का बड़ा टोला आज भी मूलभूत सुविधा पेयजल के लिए संघर्ष कर रहा है।

गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि ग्रामीणों को सुबह से लेकर देर रात तक एकमात्र कुएं के सहारे पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है, लेकिन वहां भी पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

पूरा गांव एकमात्र कुएं पर निर्भर है

ग्रामीणों का कहना है कि बड़े टोला में वर्षों से पेयजल की समस्या बनी हुई है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ संकट और विकराल हो गया है। गांव में नलकूप खनन के कई प्रयास किए गए, लेकिन अधिकांश स्थानों पर बोरिंग सफल नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप पूरा गांव एकमात्र कुएं पर निर्भर है। यही कुआं सैकड़ों लोगों और मवेशियों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत बना हुआ है।

कुएं का पानी भी पूरी तरह स्वच्छ नहीं है

ग्रामीणों के अनुसार कुएं का पानी भी पूरी तरह स्वच्छ नहीं है। मजबूरी में लोग उसी पानी का उपयोग पीने और घरेलू कार्यों के लिए कर रहे हैं। दूषित पानी के सेवन से बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है, लेकिन विकल्प नहीं होने के कारण ग्रामीण इसी पानी पर निर्भर हैं।

कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी

मामले को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अमरपुर के अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर ने भी सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे अमरपुर ब्लॉक में ऐसे कई गांव हैं जहां लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। शासन की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना धरातल पर अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है। महेंद्र ठाकुर ने कहा कि यदि जल्द ही ग्रामीणों को पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई और अधूरी योजनाओं को पूरा नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी।

एक किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा पानी

जब कुएं में पानी खत्म हो जाता है तो ग्रामीणों को गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर स्थित लखनपुर तिराहे तक जाना पड़ता है। महिलाएं और बच्चे सिर पर बर्तन रखकर पानी ढोते दिखाई देते हैं। कई परिवारों को दिन में कई बार यह दूरी तय करनी पड़ती है ताकि घर की दैनिक जरूरतें पूरी हो सकें। गांव की महिलाओं का कहना है कि पानी लाने में ही उनका अधिकांश समय निकल जाता है।

अधूरी पड़ी जल जीवन मिशन योजना

ग्रामीणों की सबसे बड़ी नाराजगी जल जीवन मिशन को लेकर है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में करीब दो वर्ष पहले जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था। कई स्थानों पर पाइप डाले गए, लेकिन आज तक घरों तक कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है। गांव में उच्च स्तरीय पानी टंकी का निर्माण कार्य भी चल रहा है, लेकिन योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

नर्मदा डैम घाट में विशेष संडे स्विमिंग आयोजित

एरोबिक्स, योग एवं सामूहिक फिटनेस गतिविधियों का भी किया गया आयोजन

डिंडोरी, नवभारत 31 मई। एसडीईआरएफ के जवानों के द्वारा ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत विशेष संडे स्विमिंग का आयोजन कलेक्टर अंजू भदौरिया के मार्गदर्शन में खेल एवं युवा कल्याण विभाग, द्वारा जिले में 5 माई से 5 जून तक 'ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण आरोह-2026' के अंतर्गत रविवार को तैराकी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर एरोबिक्स, योग एवं सामूहिक फिटनेस गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ-साथ उनके परिवारजनों एवं स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का दिया संदेश-कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में स्वास्थ्य, अनुशासन एवं सामुदायिक सहभागिता की भावना विकसित करना रहा, जिससे सभी बच्चे एवं खिलाड़ी एवं आमजन मानसिक शारीरिक सद्भावना से परिपूर्ण होंगे और स्वस्थ जीवन का आनंद लेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने उपस्थित होकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया एवं फिटनेस गतिविधियों में भाग लेकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

इनका रहा योगदान-आयोजन में विशेष सहयोग खेल और युवा कल्याण विभाग से खेल अधिकारी जिला खेल प्रशिक्षण, ब्लॉक समन्वयक मोहम्मद अहमद खान डॉ संतोष परस्ते मिथिलेश झरिया मनोज चौक से , जागेश्वर, पदवार सीआरपी कुशवाहा चेतराम अहिरवार, आरती सोंधिया, सुनीता, लक्ष्मी बनावल राजकुमार, अनीता, मार्शल आर्ट एरोबिक प्रशिक्षक आदर्श परस्ते सुनीता, प्रशिक्षक एवं खेल प्रेमियों का विशेष सहयोग रहा।

भ्रष्टाचार | सालाना 50 से 70 लाख रुपए से अधिक का खर्च सरकारी फाइलों में दर्ज होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ बेनकाब

बाघों के लिए आए बजट को खुद डकार गया बांधवगढ़ प्रबंधन

चिल्हारी, उमरिया, नवभारत। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अब बाघों के लिए सुरक्षित स्वर्ग नहीं, बल्कि प्रबंधन की घोर लापरवाही और कसीदे गढ़े गए दावों की कब्रगाह बनता जा रहा है। पनपथा बफर क्षेत्र के ग्राम खेरवा टोला में 24 मई को मृत पाए गए एक नर बाघ के पोस्टमार्टम ने पार्क प्रबंधन के उन तमाम दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, जिनमें बाघों की सेहत और सुरक्षा की बड़ी-बड़ी डींगें हांकी जाती थीं।

25 मई को तीन वन्यजीव चिकित्सकों और दो विशेषज्ञों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सामने आई है, वह केवल एक बाघ की मौत का दस्तावेज नहीं है, बल्कि वह बांधवगढ़ प्रबंधन की क्रूर संवेदनहीनता का डेथ वारंट है।

भूखा-प्यासा तड़पता रहा जंगल का राजा

आखिर करोड़ों रुपए के बजट वाले टाइगर रिजर्व में एक बाघ की यह दुर्दशा कैसे हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पन्नों को पलटिए, रिपोर्ट कह रही है कि मृत नर बाघ का स्वास्थ्य अत्यंत खराब था। सवाल उठता है कि जब बाघ की मांसपेशियां पीली और पूरी तरह सूख चुकी थीं, तो पार्क के गश्ती दल और कथित हाई-टेक मॉनिटरिंग सिस्टम को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। हद तो तब हो गई जब रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बाघ का पाचन तंत्र पूरी तरह खाली था। यानी जंगल का राजा कई दिनों से भूखा-प्यासा तड़प रहा था, जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वह लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। जब बाघ इस कदर बदहाल स्थिति में पहुंच रहा था, तब एयरकंडीशंड कमरों में बैठने वाले अफसर और जीपों में घूमने वाला स्टाफ किस गहरी नींद में सोया था? क्या इस पूरे दौरान किसी भी वनकर्मी की नजर इस बेबस बाघ पर नहीं पड़ी या फिर जानबूझकर उसकी बदहाली को छुपाया जाता रहा।

करोड़ों का बजट फिर भी बाघ कंकाल

जनता को यह जानकर हैरत होगी कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सरकार प्रति बाघ हर वर्ष लाखों-करोड़ों रुपए का भारी-भरकम बजट पानी की तरह बहाती है। बाघों के संरक्षण, उनके आहार-विहार, ट्रैकिंग, दवाओं और उनकी सुरक्षा के नाम पर सालाना करोड़ों का फंड बांधवगढ़ प्रबंधन की झोली में डाला जाता है। यदि सिर्फ एक बाघ की सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, तो उसकी मॉनिटरिंग और संरक्षण पर सालाना औसतन 50 से 70 लाख रुपए से अधिक का खर्च सरकारी फाइलों में दर्ज होता है। अब जनता पूछ रही है कि जब एक-एक बाघ पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो फिर इस बाघ का पेट खाली क्यों था, उसकी मांसपेशियां क्यों सूख गई? क्या यह करोड़ों का बजट सिर्फ कागजी बाघों को पालने और अफसरों की सुख-सुविधाओं की भेंट चढ़ रहा है? इस बाघ की खोखली हो चुकी देह ने साफ कर दिया है कि जमीनी हकीकत पर खर्च शून्य है और भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं।

जंगल में जानवरों की पेयजल व्यवस्था है लुन्ज-पुन्ज

जंगल के तालाब पोखरों में पानी नही होने के कारण जंगली जानवरों को पीने का पर्याप्त पानी नही मिलता जो जानवरों के बीमारी एवं कमजोर होने का प्रमुख कारण है नवभारत को मिली जानकारी अनुसार पहले जंगल मे बने तालाबों पोखरों में टैंकर से पानी प्रतिदिन डाला जाता था जिससे जानवरों को पर्याप्त पेयजल मिलता था किन्तु इन दिनों टैंकर से पानी नही छोड़ा जाता जिससे जंगली जानवर प्यास से भी मरते हैं जिन्हें आपसी दावन्द बताकर विभाग पल्ला झाड़ लेता है वन मंत्री एवं प्रदेश के मुखिया ध्यान दें।

कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेल्योर या सिस्टम का फेल्योर

विशेषज्ञों के अनुसार, बाघ के महत्वपूर्ण अंगों में द्यकंजेस्टिव एवं हेमरेजिकद्य परिवर्तन पाए गए हैं, जो कमजोर रक्त संचार को दर्शाते हैं। प्राथमिक तौर पर मौत की वजह कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर (हृदय और श्वसन तंत्र का ठप होना) बताई गई है, लेकिन असलियत में यह बाघ के दिल का फेल्योर नहीं, बल्कि बांधवगढ़ के पूरे प्रशासनिक तंत्र का फेल्योर है। हालांकि, स्टेट वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक हेडक्वार्टर (एसडब्ल्यूएफएच) जबलपुर में के डायरेक्टर और एनटीसीए के प्रतिनिधियों की मौजूदगी वीडियोग्राफी के साथ शव को जबलपुर ले जाकर 25 मई को ही पंचतत्व में विलीन कर दिया गया और नमूनों को एडवांस लैब भेजा गया है, लेकिन राख के नीचे इस कड़वे सच को दबाया नहीं जा सकता। बांधवगढ़ प्रबंधन अब इन एडवांस लैब्स की रिपोर्ट की आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा है, ताकि टॉक्सिसिटी (विषाक्तता) या अन्य बीमारियों का बहाना बनाकर अपनी चमड़ी बचा सके।

अपनी नाकामी छुपाने के लिए शव पर दागा डार्ट!

प्रबंधन की चालबाजी की इंतहा देखिए, पोस्टमार्टम में यह बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक खुलासा हुआ है कि बाघ के दाहिने कंधे पर जो ट्रैंक्विलाइजर डार्ट लगा हुआ था, वहां कोई रक्तस्राव (ब्लीडिंग) नहीं पाई गई। चिकित्सा विशेषज्ञों ने साफ कर दिया कि यह डार्ट बाघ की मौत के बाद लगाया गया था। यह सीधे तौर पर एक संगीन अपराध और सबूतों से छेड़छाड़ का मामला है। अपनी गर्दन बचाने और यह दिखाने के लिए कि हमने तो बाघ को बचाने का प्रयास किया था, प्रबंधन ने एक मृत शव पर डार्ट दाग दिया। इस घिनौनी करतूत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए?